Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान के अनुसार, संघ के लिए संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होंगे।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (d)

अनुच्छेद 79:

संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोक सभा होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। यहाँ कार्यकारी और विधायिका का कठोर पृथक्करण देखा जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान कहता है कि राज्यों की परिषद (राज्य सभा) में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
2. राज्यसभा के सेवानिवृत्त मनोनीत सदस्य अधिकतम तीन बार पुन: नामांकन के लिए पात्र होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (d)

संविधान कहता है कि राज्यों की परिषद में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस तरह से चुना जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा वर्णित करती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुन: चुनाव और नामांकन के लिए पात्र होते हैं। इसपर कोई प्रतिबंध नहीं है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल छह वर्ष निर्धारित किया जाता है।
2. अधिकृत होने के बावजूद, संसद ने संसद की सदस्यता के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (d)

संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है तथा इसे संसद पर छोड़ दिया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद की सदस्यता के लिए संवैधानिक योग्यता के अलावा संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) में कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ सम्मिलित की हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान () कर सकते हैं।
2. राज्य सभा के सभापति के पास मत डालने का अधिकार होता है (बराबर के मामले में, जब उप-राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (b)

भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान (prorogue) कर सकते हैं, लेकिन केवल लोकसभा को भंग (dissolve) कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

सभापति को बोलने का अधिकार होगा, और अन्यथा, जब उप-राष्ट्रपति को उनके कार्यालय से हटाने का कोई भी प्रस्ताव परिषद में विचाराधीन हो, राज्य सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन यह अनुच्छेद 100 से संबंधित नहीं होगा तथा इस तरह की कार्यवाही के दौरान इस तरह के संकल्प या किसी अन्य मामले पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान संसद के दोनों सदनों के लिए समान (common) पदों (सचिवीय कर्मचारियों) के सृजन के लिए एक कठोर रोकथाम हेतु प्रावधान प्रदान करता है।
2. सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (b)

अनुच्छेद 98 (1)

संसद के प्रत्येक सदन में एक पृथक सचिवीय स्टाफ होगा:
बशर्ते कि संसद के दोनों सदनों में समान पदों के सृजन को रोकने के रूप में इस खंड में कुछ भी नहीं कहा गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 100 (1)

संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालेगा।

अध्यक्ष या सभापति, या इस तरह के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होंगे, जो पहली बार में मत नहीं डालेंगे, लेकिन मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालेंगे।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.6) सदन के कार्य संचालन के स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, आवश्यक और सार्वजनिक महत्व का हो
2. यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए।
3. इसे किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.6) Solution (d)

स्थगन प्रस्ताव संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है

यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, जरूरी और सार्वजनिक महत्व का हो

इसलिए कथन 1 सही है।

यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए।

इसलिए कथन 2 सही है।

इसे किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या धन विधेयक पर लागू होती है।

2. राज्यसभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (c)

संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होती है, न कि धन विधेयकों या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, तो राज्यसभा के उप सभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्य सभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारित व्यय (charged expenditure) संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य होता है
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आती है।
3. ऋण, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.8) Solution (d)

भारित व्यय संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है, इसपर केवल संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की केवल पेंशन भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

ऋण, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आता है।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.9) निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खाते (Public Account) में जमा किया जाता है?

1. भविष्य निधि जमा
2. ट्रेजरी बिल जारी करके संग्रहित ऋण
3. प्रेषण (Remittances)

4. बचत बैंक जमा

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 3
b) केवल 1, 3 और 4
c) केवल 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.9) Solution (b)

भारत का सार्वजनिक खाता: भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन (भारत के समेकित निधि में जमा किए गए धन के अतिरिक्त) को भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा।

इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण शामिल होते हैं।

Q.10) भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तथा वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।
2. इस निधि में समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशि को जमा किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (d)

इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तथा वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान ने 'भारत की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया है, जिसमें कानून द्वारा निर्धारित राशियों को समय-समय पर जमा किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों को पांच वर्ष के लिए चुना जाता है।
2. भारत अब तक सुरक्षा परिषद का कभी भी गैर-स्थायी सदस्य नहीं रहा है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (d)

भारत को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव दो वर्ष के लिए होता है - इसलिए प्रत्येक वर्ष महासभा कुल 10 में से पाँच गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।

भारत इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रहा है।

Source: https://indianexpress.com/article/explained/what-are-non-permanent-seats-in-the-un-security-council-and-how-are-they-filled-6465539/

Q.2) 'तूलिनी महोत्सव' (Tulini Festival) किसके द्वारा मनाया जाता है

a) अपातानी जनजाति
b) सुमी जनजाति
c) डोंगरिया-कोंध जनजाति
d) चेंचू जनजाति

Q.2) Solution (b)

तुलिनी महोत्सव भाई-चारा, एकजुटता, साझाकरण और एकता का प्रतीक है, जो केवल सुमी समुदाय के बीच ही नहीं बल्कि पूरे नागों के बीच है।

सुमी जनजाति - नागालैंड

Q.3) 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' (PM Svanidhi) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह रेहड़ी, पटरी विक्रेताओं (street vendors) को-10,000 तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है।
2. इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (a)

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि, या प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना आरंभ की, जो 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रु. तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है, जिनका 24 मार्च को या उससे पहले कारोबार संचालन में था। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है।

Source: https://www.livemint.com/news/india/centre-launches-scheme-for-street-vendors-to-get-loans-of-up-to-rs-10-000-11591015442185.html

Q.4) 'सिविल सेवा बोर्ड' (Civil Services Board) का नेतृत्व कौन करता है

a) राज्य का राज्यपाल
b) राज्य के मुख्य सचिव
c) मुख्यमंत्री
d) कैबिनेट सचिव

Q.4) Solution (b)

नियमों के अनुसार, सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानान्तरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड को अपने निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने से पहले एक सिविल सेवक के स्थानांतरण पर निर्णय लेना अनिवार्य है। नियम सिविल सेवा बोर्ड को 1 जनवरी को केंद्र सरकार को उनके द्वारा आयोजित बैठकों की तारीख के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तथा साथ ही, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने के लिए भी अनिवार्य करते हैं।

सिविल सेवा बोर्ड का नेतृत्व एक राज्य के मुख्य सचिव करते हैं तथा इसमें वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव या अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, वित्तीय आयुक्त या सदस्य के रूप में समकक्ष रैंक और पद के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा, इसके सदस्य सचिव के रूप में राज्य सरकार में कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे।

राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही को बचाने के लिए तथा राजनीतिक आकाओं द्वारा सिविल सेवकों के लगातार स्थानान्तरण को समाप्त करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे नौकरशाहों के स्थानान्तरण और पोस्टिंग पर विचार करने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करें।

Source: https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-are-punjab-congress-leaders-up-against-cbs-notification-6464873/

Q.5) 'कानून का शासन सूचकांक' (Rule of Law Index) किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है

a) विश्व न्याय परियोजना (World Justice Project)
b) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
c) अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
d) इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेन्स यूनिट (Economist Intelligence Unit)

Q.5) Solution (a)

विश्व न्याय परियोजना (World Justice Project) कानून का शासन सूचकांक एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है, जो इस बात का विस्तृत और व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि देश किस हद तक कानून के शासन का पालन करते हैं। सूचकांक कानून के शासन के आठ आयामों पर डेटा प्रदान करता है: सीमित सरकारी शक्तियां; भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति; व्यवस्था और सुरक्षा; मौलिक अधिकार; खुली सरकार; विनियामक प्रवर्तन; नागरिक न्याय; और आपराधिक न्याय।

Source: https://www.thehindu.com/news/national/decide-on-plea-on-rule-of-law-index-in-6-months-supreme-court-tells-government/article31863917.ece